

अध्याय – 3

सुधार उपाय और नीति प्रस्तावना

देश में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है। दिनांक 20 परवरी, 2009 को भारत सरकार ने कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति घोषित की। इस राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य कार्य संबंधी चोट, रोग, आपदा और राष्ट्रीय संपत्ति की हानि में निरन्तर कमी करना है। नीति में प्रस्तावना, लक्ष्य उद्देश्य के साथ प्रावी प्रवर्तन, राष्ट्रीय मानकों का विकास, उचित माध्यमों द्वारा मानकों के साथ अनुपालन संवर्धन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दक्षता विकास जैसे कार्यवाई कार्यक्रम शामिल हैं। संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के आयोजन से विभिन्न पणधारियों द्वारा राष्ट्रीय नीति क्रियान्वित की जा रही है। नीति के प्रावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार, पणधारियों के साथ मिलकर उचित कार्यवाई के कार्यक्रमों को प्रारंभ कर रही है।

संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकृत विभिन्न कन्वेंशनों, संलेखों को प्रावी बनाने के लिए कृतसंकल्प है। इन मानकों को विधि या विनियमों में समाहित कर, सामूहिक करार, व्यवहार संहिता आदि से अंगीकार किया जाता है। 43 कन्वेंशनों और 1 संलेख (प्रोटोकॉल) का अनुमोदन भारत कर चुका है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आई.एल.ओ. के दस्तावेज नामतः व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1981 (नं. 155) एस्बेस्टॉस कन्वेंशन, 1986 (नं. 162), रसायन कन्वेंशन 1990, (नं. 170) भारत सरकार के पास सुधार के लिए सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

भारत सरकार के पास निम्नलिखित स्कीमों की पूर्ति 12वीं पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है:-

- डीजीपासली संगठन का सुदृढ़ीकरण और कारखानों व पत्तनों में व्या.सु. और स्वास्थ्य
- एम एस एम ई में सुरक्षा प्रणाली तथा रसायन प्रक्रिया एककों में क्षेत्रीय श्रम संस्थान, परीदाबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करना
- भारत में सिलिकॉसिस और एसबेस्टॉसिस की पहचान, उन्मूलन और नियंत्रण
- शिलांग में क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना (एन ई आर)

सुधार संबंधित उपाय एवं नीतिगत पहल

जा-1 सुरजा महाविदेशालय जा-1 अधिनियम, 1952 के प्रावधानों एवं उससे तैयार किए गए नियमों और विनियमों को लागू करता है। इन नियमों/विनियमों/अधिनियम के तहत उठाए जा रहे आवश्यक संविधि उपाय को समय-समय पर जा-1 की जरूरतों हेतु संशोधित करने की जरूरत है जिससे कि जा-1 उद्योग के बदलते परिदृश्य के साथ ज़रूरत से ज़रूरत मिलाकर चला जा सके।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ज़ोयला जा-1 विनियम, 1957 धातु जा-1 विनियम, 1961 तथा तेल जा-1 विनियम, 1984 में सुधार/बदलाव किए गए हैं, ताकि वर्तमान विनियम को जा-1 विनियमों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके। संशोधन प्रक्रियाधीन है। जा-1 अधिनियम, 1952 में सुधार/बदलाव भी प्रक्रियाधीन है।

श्रम कल्याण निधियां

सरकारी (क.रा.बी. सहित) और गैर-सरकारी स्वास्थ्य प्रदाता जो भर्ती तथा/अथवा दैनिक देख-रेख सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, राज्य सरकार तथा बीमाकर्ताओं के बीच पैनाल के लिए हुई सहमति के अनुसार ऐसी आवश्यकताओं के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।

बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 वयस्क तथा बाल बंधुआ पद्धति के बीच जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। पुरुष/महिला बंधुआ श्रमिकों से संबंधित अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता।

योजनाएं

अनुसंधान अध्ययन अत्यधिक नीतिगत जानकारी प्रदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ अनुकूल कामकाजी दशाओं के संबंध में कामगारों के कल्याण को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रमों तथा योजनाओं को बनाने के दृष्टि से गहन अनुसंधान जांच की भी जरूरत प्रतीत होती है। अतः यह देखा जा सकता है कि आगामी वर्षों में हमें भावी नीतियों, कार्यक्रमों तथा उनके क्रियान्वयन के लिए अच्छे अनुसंधान कार्य की जरूरत होगी। यह विवेकपूर्ण होगा कि मंत्रालय की सहज जरूरतों पर आधारित समस्या क्षेत्रों का पता लगाया जाए तथा विख्यात अनुसंधान संगठनों को अध्ययन का काम सौंपा जाए।

सुधारात्मक उपाय एवं नीति संबंधी प्रयास

प्रशिक्षण

I. “पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ओं (औ.प्र.सं.) की स्थापना” -नामक के-द्व प्रवर्तित योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2000 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के समाजार्थिक विकास हेतु एक कार्यसूची की घोषणा की जिसमें अनेक बातों के साथ-साथ अजले तीनों वर्षों में -ए व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ओं को दोषु-ए करने-ए शामिल था।

इस योजना की अवधि अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2010 तक की थी और इस प्रकार यह योजना 31 मार्च, 2010 को समाप्त करने दी गई।

II. जौशल विकास पहल योजना (एस डी आई एस)

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के अनुसरण में जल्दी स्कूली शिक्षा छोड़ देने वालों तथा वर्तमान कामचारों के लिए उद्योग, राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञों के निजट परामर्श से जौशल विकास हेतु एक -ए कार्यनीति के ढांचे का विकास किया है। व्यय वित्त समिति तथा आर्थिक कार्य हेतु मंत्रिमंडल समिति ने क्रमशः 19.02.2007 तथा 24.05.2007 को योजना को अनुमोदन प्रदान करने दिया है। एस डी आई योजना के कार्यावधि का कार्य मई 2007 से आरंभ किया गया था। पांच मिलियन व्यक्तियों के प्रशिक्षण/परीक्षण के लक्ष्य के साथ परियोजना अवधि अप्रैल, 2012 से मार्च 2017 है।

जौशल विकास हेतु -ए ढांचे की मुख्य विशेषताएं हैं :

- I. उद्योग के परामर्श से मॉड्यूलर नियोजनीय जौशलों (एम ई एस) के आधार पर मांज आधारित अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। एम ई एस ‘-यू-तम जौशल सेट’ है जोकि लाभप्रद रोजगार हेतु पर्याप्त है।
- II. विभिन्न लजित समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीली वितरण प्रणाली (अंशजालिक, सप्ताहांत, पूर्णजालिक, ऑन साइट/ऑफ साइट)।
- III. विभिन्न लजित समूहों की मांज को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों के कार्यक्रम (मूल पाठ्यक्रम एवं जौशल उन्नयन)।
- IV. सरकारी, निजी क्षेत्र और औद्योगिक स्थापनों के अधीन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपीज) द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- V. प्रशिक्षण को लाजत प्रभावी बनाने के लिए विद्यमान अवसर-ए का इष्टतम उपयोग।
- VI. यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षण भेदभाव रहित हो, प्रशिक्षण वितरण में शामिल -ए होने वाले स्वतंत्र मूल्यांकन निजाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के जौशलों का परीक्षण।

VII. उ-1 व्यक्तियों, जि-होंने 5वीं ज्जा पूरी ज्ज ली है और जो पढ-ने-लिज-ने में सज्म हैं, जे लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

VIII. योज-11 ज्जा सार तत्व प्रमाज-1 में है जिसज्जी राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय रूप में मा-यता है।

III. 500 औद्योगिज प्रशिजज संस्था-गों ज्जा उत्तृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-1

जे-द्रीय वित्त मंत्री -ने अप-ने बजट भाषज 2004-2005 तथा पु-1: 2005-06 में देश में 500 औद्योगिज प्रशिजज संस्था-गों जे उन्नय-1 हेतु उपायों ज्जी घोषजा ज्जी। तत्पश्चात, वित्त मंत्री जे परामर्श जे अ-गुरुप, 100 औद्योगिज प्रशिजज संस्था-गों ज्जा घरेलू संसाध-गों तथा 400 औद्योगिज प्रशिजज संस्था-गों ज्जा विश्व बैंज सहायता जे माध्यम से उन्नय-1 ज्ज-ने हेतु जर्जवाई ज्जी जई।

बहु-जौशल पाठ्यक्रमों ज्जी मुख्य विशेषताएं निम्नलिजित हैं :

- अवसंरच-11 सुविधाएँ प्रदा-1 ज्ज, जि-सी औद्योगिज प्रशिजज संस्था-1 जे आस-पास उद्योज जे विशेष समूह ज्जी मांज ज्जे पूरा ज्ज-ने जे लिए बहु-जौशल पाठ्यक्रम आरंभ ज्ज-जे विश्व स्तर ज्जा बहु-जौशल्युक्त जर्जबल तैयार ज्ज-ने जे लिए उत्तृष्ट जे-द्रों (सीओई) जे रूप में औद्योगिज प्रशिजज संस्था-गों ज्जा उन्नय-1।
- योज-11 ज्जी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रज्जार हैं:
 - एज वर्षीय व्यापज आधारित बु-नियादी प्रशिजज (बीबीबीटी) पाठ्यक्रम, तत्पश्चात 6 माह ज्जी अवधि जे उच्च माड्यूलर पाठ्यक्रम आरंभ ज्ज-11।
 - छह माह जे विशिष्ट माड्यूल, मुख्यतया उद्योज में (शॉप फ्लोर प्रशिजज)।
 - बहु-आजत तथा बहु-निर्जम प्रावधा-1।
 - उद्योजवार समूह दृष्टिज्जेज।
 - प्रशिजज जे समस्त पहलुओं में उद्योज ज्जी अपेजाजृत अधिज एवं सज्जिय भाजीदारी सु-निश्चित ज्ज-ने जे लिए संस्था-1 प्रबंध-1 समिति (आईएमसी) जे रूप में सार्वजजिज-निजी भाजीदारी।

IV. 100 औद्योगिज प्रशिजज संस्था-गों ज्जा उत्तृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-1

योज-11 ज्जा उद्देश्य विश्व स्तर ज्जा बहु-जौशल जर्जबल तैयार ज्ज-ने हेतु वर्तमा-1 100 सरजारी औद्योगिज प्रशिजज संस्था-गों ज्जा उत्तृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-1 ज्ज-11 है।

व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) -ने 15 फरवरी 2005 ज्जे हुई अप-नी बैठज में योज-11 ज्जी संस्तुति ज्जी। आर्थिज जर्ज्यों हेतु मंत्रिमंडल समिति -ने 16 मार्च 2005 ज्जे हुई अप-नी बैठज में योज-11 ज्जे अ-गुमोद-1 प्रदा-1 जि-या। घरेलू संसाध-गों से वित्तपोषित जि-ए जा-ने वाले 100 औद्योगिज प्रशिजज संस्था-1 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में (जम्मू व जश्मीर, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों से इतर) इ-1 राज्यों में सरजारी औद्योगिज प्रशिजज संस्था-गों ज्जी संज्या जे अ-गुपात में बंटे हैं। योज-11 ज्जी जुल लाजत 160 ज्जरोड़ रुपए है, जिसमें से

जे-द्र तथा राज्य सरकार जे बीच लाजतभाजिता जे 75:25 जे प्रतिरूप पर जे-द्र सरकार जा अंशदा-1 120 ज़रोड़ रुपए है।

जि सी विशेष जेत्र में समस्त आईटीआईज में प्रशियज पहले से आरम्भ हो जया है। योज-11 जी अवधि अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2010 तज थी और इस प्रजार यह योज-11 31 मार्च, 2010 जे समाप्त ज़र दी जई।

विश्व बैंक सहायित व्यावसायिज सुधार परियोज-11 (वी टी आई पी) जे साथ 400 औद्योजिज प्रशियज संस्था-गों ज़ा उन्नय-1

विश्व बैंक जी सहायता से उन्नय-1 जिए जा-ने वाले 400 औद्योजिज प्रशियज संस्था-गों में से 100 औद्योजिज प्रशियज संस्था-गों जे वित्त वर्ष 2006-07 जे दौरा-1 तथा 150 औद्योजिज प्रशियज संस्था-1 2007-08 और 2008-09 जे दौरा-1 चु-ने जए थे।

विश्व बैंक जे साथ 02.11.2007 जे ज़रार पर हस्ताजूर जिए जए थे और इसजे बंद हो-ने जी तिथि दिसम्बर, 2012 है। भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा दिसम्बर, 2012 से आजे अर्थात -नवम्बर, 2014 तज अ-य 23 मही-गों जे लिए परियोज-11 में जेई अ-य लाजत विस्तार -1 हो-ने जे लिए ज़रार पर हस्ताजूर जिए जए हैं।

33 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा जे-द्र सरकार द्वारा योज-11 ज़ा ज़ार्या-वय-1 जिया ज़ा रहा है। राज्य सरकारों -ने परियोज-11 अवधि जे दौरा-1 तथा बाद में योज-11 जे ज़ार्या-वय-1/सततता जे लिए प्रतिबद्धता, संस्था-1 प्रबंध-1 समिति (आई एस सी) जे सशक्तिजूरज, औद्योजिज प्रशियज संस्था-गों जे प्रधा-1चार्यो जी शक्तियों में वृद्धि, तथा हेतु समझौता-ज्ञाप-1 (एम ओ यू) पर हस्ताजूर जिए।

V. सार्वजनिज-निजी भाजीदारी जे माध्यम से 1396 सरजारी औद्योजिज प्रशियज संस्था-गों ज़ा उन्नय-1

देश में 1896 सरजारी औद्योजिज प्रशियज संस्था-गों (1.1.2007 जी स्थिति जे अनुसार) में से 500 सरजारी औद्योजिज प्रशियज संस्था-गों ज़ा वर्ष 2005-06 से आरंभ योज-11 जे तहत उत्तृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-1 जिया ज़ा रहा है। मा-1नीय वित्त मंत्री -ने वर्ष 2007-08 जे अप-ने बजट अभिभाषज में सार्वजनिज निजी भाजीदारी जे माध्यम से शेष 1396 सरजारी औद्योजिज प्रशियज संस्था-गों ज़ा उत्तृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-1 ज़र-ने जी घोषजा जी। तद-गुरूप , 3550 ज़रोड़ रु. (2.5 ज़रोड़ रु. प्रति औद्योजिज प्रशियज संस्था-1 जी दर से 1396 औद्योजिज प्रशियज संस्था-गों जे उन्नय-1 हेतु 3490 ज़रोड़ रु. तथा योज-11 जे प्रबंध-1, प्रबोध-1 तथा मूल्यांज-1 हेतु 60 ज़रोड़ रु.) ज़ा जुल परिव्यय तैयार जिया जया है।

योज-11 ज़ा उद्देश्य प्रशियज जी रूपरेजा एवं सुपुर्दजी जे और अधिज माँज प्रभावी ब-1ाजूर व्यावसायिज प्रशियज प्रजाली जे स्-1ातजों जे रोजजार परिजामों में सुधार ज़र-11 है।

- O उन्नय-1 जिए जा-ने वाले प्रत्येज औद्योजिज प्रशियज संस्था-1 जे लिए उन्नय-1 जी प्रजिया ज़ा -नेतृत्व ज़र-ने जे लिए एज उद्योज भाजीदार जे शामिल जिया ज़ाएजा। उद्योज संघों जे परामर्श से राज्य सरकार द्वारा उद्योज भाजीदार ज़ा चय-1 जिया ज़ाएजा।

- 0 प्रत्येक चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ए हेतु संस्था-ए प्रबंध-ए समिति(आईएमसी) जे जठ-ए/ पुनर्जठ-ए जिया जाएजा, इसमें अध्यक्ष के रूप में उद्योग भाजीदार या उ-ए प्रतिनिधि, उद्योग भाजीदार द्वारा -नामित किए जाने वाले स्थानीय उद्योग के चार सदस्य, राज्य सरकार द्वारा -नामित किए जाने वाले पाँच सदस्य, पदे-ए सदस्य सचिव के रूप में प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ए शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा संस्था-ए प्रबंध-ए समिति को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
- 0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ए के कार्य-ए जे प्रबंध-ए कर-ए के लिए आई एम सी को वित्तीय एवं शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। संस्था-ए प्रबंध-ए समिति को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ओं में 20% तज प्रवेश निर्धारित कर-ए की भी अनुमति दी जाएगी।
- 0 के-ए सरकार द्वारा संस्था-ए प्रबंध-ए समिति को प्रत्येक रूप से 2.5 करोड़ रुपए तज जे ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा जिसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ओं जे उन्नय-ए कर-ए हेतु निधियों जे उपयोग कर-ए की शक्तियाँ प्रदान की जाएगी।
- 0 ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी संस्था-ए प्रबंध-ए समिति द्वारा की जाएगी। ऋण लौटाने के लिए 10 वर्षों की अधिस्थान-ए अवधि होगी तथा तत्पश्चात ऋण जे भुजता-ए 20 वर्षों की अवधि के दौरान एक समा-ए वार्षिक छिस्तों में किया जाएगा।
- 0 राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ए के स्वामी के रूप में ब-ए रहेगी और 20% तज प्रवेश, जिसके निर्धारण कर-ए की अनुमति संस्था-ए प्रबंध-ए समिति को होती है, के सिवाए प्रवेश एवं शुल्कों जे विनियम-ए जारी रहेगी।

आर्थिक कार्यों हेतु मंत्रिमंडल समिति -ए वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान 2,800 करोड़ रु. के परिव्यय सहित 1096 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ओं के उन्नय-ए हेतु योज-ए को दिनांक 03.10.2008 को हुई अप-ए बैठक में मंजूरी दे दी है।

योज-ए को 50.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बारहवीं योज-नावधि के दौरान जारी रज-ए के लिए एसएफसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

VI. महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम-

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जे उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण योज-ए के माध्यम से महिलाओं जे समाजार्थिक विकास कर-ए है।

के-द्रीय क्षेत्र के तहत, -एएडा में एक राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था-ए (ए-वीटीआई) तथा मुंबई, बंजलौर, तिरुव-ंतपुरम, पा-पीपत, जेलजता, तुरा, इलाहाबाद, इंदौर, वडौदरा एवं जयपुर में 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था-ए (आरवीटीआईज) की स्थाप-ए की गई है।

ये संस्था-ए शिल्प-ए प्रशिक्षण योज-ए और शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योज-ए के तहत ए-सीवीटी द्वारा अनुमोदित जौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं।

सी. एल. एस. - II

दसवीं पंचवर्षीय योजना में सीजीआईटी की न्यायनिर्णयन व्यवस्था में लोक अदालतों की वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरूआत की गई थी जिसे 11वीं योजना में व्यवस्था का अनिवार्य अंग बनाया गया है। इसका उद्देश्य है-औद्योगिक विवादों का त्वरित निपटान। जो मामले अपेक्षाकृत कम जटिल हैं, उनका न्यायनिर्णयन लोक अदालतों के माध्यम से किया जाता है। तथापि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विवाद से जुड़े पक्ष इस प्रक्रिया से मामले को निपटाने के लिए कितने तैयार हैं। सीजीआईटी के पीठासीन अधिकारी सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाते हैं।

2. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी की रिक्ति उत्पन्न होने के मामले में न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारियों के बीच सम्पर्क अधिकारियों की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए सभी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन समय-समय पर आयोजित किया जाता है।

3. न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को श्रमिक हित में और सुदृढ़ बनाने हेतु, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में निम्नांकित संशोधन किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औद्योगिक अशांति को नियंत्रित करने हेतु श्रमिकों को प्रभावी और समय पर न्याय उपलब्ध हो।

(i) धारा 2-क को संशोधित किया गया है और इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि विवाद के निपटान हेतु, समुचित सरकार के संराधन अधिकारी को आवेदन देने के पैंतालीस दिनों के उपरांत, संदर्भित विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु कामगार, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में सीधे आवेदन दे सके तथा ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु शक्तियां और क्षेत्राधिकार उसी प्रकार प्राप्त होंगे मानो उसे यह विवाद समुचित सरकार द्वारा संदर्भित किया गया हो।

(ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11 को भी संशोधित किया गया है जिससे श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा जारी अथवा इसके समक्ष लाये गये प्रत्येक पंचाट अथवा आदेश अथवा निपटान पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के तहत सिविल अदालत के आदेशों अथवा डिक्री पर अमल के लिए निर्धारित कार्यवाही के अनुसार कार्य करेंगे। साथ ही, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण किसी क्षेत्राधिकार वाली सिविल अदालत को पंचाट, आदेश अथवा निपटान से अवगत कराएगा तथा ऐसी सिविल अदालत उस पंचाट, आदेश अथवा निपटान को उसी प्रकार कार्यान्वित करवाएगी मानो वह डिक्री उसी के द्वारा पारित की गई हो।

समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड

श्रमजीवी पत्रकार तथा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 श्रमजीवी पत्रकार तथा समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में नियोजित अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तों से सरोकार रखता है। इस अधिनियम की धारा 9 और 13 में अन्य बातों के साथ-साथ, क्रमशः श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर-पत्रकार समाचार पत्र/समाचार एजेंसी कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी दरों के निर्धारण तथा संशोधन के लिए वेतन बोर्डों के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार, वेतन बोर्डों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (i) समाचारपत्र प्रतिष्ठान के संबंध में नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति।
 - (ii) धारा 9 के अंतर्गत वेतन बोर्ड के लिए श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति तथा अधिनियम की धारा 13-ग के अंतर्गत वेतन बोर्ड हेतु गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति।
 - (iii) चार स्वतंत्र व्यक्ति, जिन में से एक व्यक्ति वह होगा जो उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो और जिसे केन्द्र सरकार द्वारा उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- यह अधिनियम, वेतन बोर्डों के गठन के लिए अवधि का निर्धारण नहीं करता। ऐसे कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों का गठन वर्ष 1956, 1963, 1975, 1985 तथा 1994 में किया गया था।
 - सरकार ने दिनांक 24.05.2007 के भारत के राजपत्र (असाधारण) का.आ. संख्या 809 (अ.) और 810 (अ.) में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 9 और 13-ग के अंतर्गत क्रमशः दो नए वेतन बोर्ड—एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तथा दूसरा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए न्यायमूर्ति कुरूप की अध्यक्षता में गठित किए थे। वेतन बोर्डों को अपनी रिपोर्ट संघ सरकार का प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया गया था। वेतन बोर्ड, दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय से कार्य कर रहे थे।
 - सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों के परामर्श से अधिसूचना का. आ. संख्या 2524 (अ.) और का. आ. संख्या 2525 (अ.) दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 द्वारा पत्रकारों तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों एवं समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए 8 जनवरी, 2008 से मूल मजदूरी के 30% की दर पर मजदूरी की अंतरिम दरें प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी।

- सरकार ने न्यायमूर्ति कुरुप, जिन्होंने 31.07.2008 से त्याग पत्र दे दिया था, के स्थान पर मुंबई उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया को दोनों ही वेतन बोर्डों के एक श्रमजीवी पत्रकारों हेतु और दूसरा गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए, समान्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति ने दिनांक 04.03.2009 को कार्यभार संभाल लिया।
- चूंकि श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों ने निर्धारित समय के अंदर अर्थात् दिनांक 23 मई, 2010 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, अतः सरकार ने अधिसूचना का. आ. 1304 (अ.) और 1305 (अ.) दिनांक 2 जून, 2010 द्वारा न्यायमूर्ति गुरबक्श राय मजीठिया की अध्यक्षता में श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों के कार्यकाल का 31 दिसम्बर, 2010 तक विस्तार कर दिया ताकि बिना किसी और समय विस्तार के वेतन बोर्ड 31 दिसम्बर 2020 को अथवा इससे पूर्व अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान कर सकें।
- वेतन बोर्डों ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31-12-2010 को प्रस्तुत कर दी। मंत्रिमंडल ने समाचार पत्र प्रतिष्ठानों और समाचार एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों की, इस मंत्रालय की दिनांक 7 अक्टूबर, 2011 की मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी में यथानिहित सिफारिशें स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव, 25 अक्टूबर, 2011 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया।
- मजीठिया वेतन बोर्डों की सिफारिशें, सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं और का.आ.सं. 2532 (अ.) दिनांक 11.11.2011 द्वारा सरकारी राजपत्र में एबीपी प्राईवेट लि बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 2011 की डब्ल्यूपी (सी) सं. 246 के परिणाम के अध्यक्षीन अधिसूचित की गई थीं। ये सिफारिशें इस मंत्रालय के वेबसाइट में अपलोड कर दी गई हैं और सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में हैं।
- चूंकि सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में विहित है, अतः अधिसूचनाओं के प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई थी। अधिसूचना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने की दृष्टि से प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्तर की अनुवीक्षण समिति स्थापित की गई है। केन्द्रीय स्तर की अनुवीक्षण समिति की प्रथम बैठक 7 दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए 24.09.2012 को हैदराबाद में हुई थी।

परिणामी बजट 2013-14

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिचय 2013-14			परिमाण्य/सुपुर्दगीय /वास्तविक परिणाम	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं / समयपर कता	अभ्युक्तियां/जोखिम के कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			योजनेतर बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास (योजना)	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के सरकारी एजेंडा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की योजना स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि सरकारी कार्यचालन में पारदर्शिता लाई जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में कम्प्यूटरीकरण के प्रयास की शुरुआत तथा कार्यक्षमता में सुधार करना है।		200.00		इन्हें किसी वास्तविक संख्याओं के रूप में परिमाणित नहीं किया जा सकता है। डाटाबेस तैयार करने के रूप में तथा शीघ्र सूचना की प्राप्ति जैसे लाभ प्राप्त किए जा सकेंगे जिससे बेहतर एवं समयबद्ध निर्णय लिए जाएंगे।	बाल श्रम योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन अनुदान जारी करना। सभी केन्द्रीय श्रमायुक्त कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ना। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अनुबंधित सलाहकारों का भुगतान।		लैन का विस्तार, कम्प्यूटरीकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ना, तकनीकी कुशलता का अद्यतनीकरण, साफ्टवेयर चलाने तथा नेटवर्क प्रबंधन आदि।

भविष्य निधि संगठन

जं प्यूटरीजरज परियोज-ग

त्वरित विज्ञान जे चरज चर्य में वृद्धि जे ध्या-ग में रजते हुए, अभिदाताओं एवं नियोक्ताओं जे प्रभावी, सुजम एवं समय पर सेवाएं उपलब्ध जरा-गे जी चु-गैतियों से निपट-गे जे लिए एज जं प्यूटरीजरज परियोज-ग जे लज्य एज पारदर्शी एवं प्रतिसंवेदी वातावरज जी सुविधा प्रदा-ग जर-ग है जोकि सभी ई-जव-र्गस परियोज-गओं जे सार है। इस परियोज-ग जे राष्ट्रीय सूच-ग विज्ञान जे-द्र (ए-ग.आई.सी.) जे सहयोज से चरजबद्ध तरीजे से लाजू जिया जे रहा है।

अ-य योज-गबद्ध सेवाएं: त्वरित एवं अधिज प्रभावी सेवाओं में वृद्धि जर-गे जे लिए कुछ अ-य सेवाओं जी भी योज-ग ब-गई जई है:-

- ज) वेबसाईट जे माध्यम से सदस्य पंजीजरज
- ज) नियोक्ताओं द्वारा रिट-गों जे इलैक्ट्रानिज रुप में जमा जर-ग
- ज) गैट बैंजिज जे माध्यम से अंशदा-ग जी प्राप्ति
- घ) ए-ग.ई.एफ.टी. मोड द्वारा भुजता-ग